अम्बेडकर नगर में कृषि यंत्रीकरण के कारण अनुसूचित जाति श्रमिकों के प्रवासन के पैटर्न

अमन वर्मा एवं सुधांशु वर्मा

https://doi.org/ 10.61410/had.v21i2.297

सार (Abstract):

प्रस्तुत शोध अध्ययन उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जनपद में कृषि यंत्रीकरण की प्रक्रिया एवं उसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति के कृषि श्रमिकों में उत्पन्न प्रवासन के पैटर्न का विश्लेषण करता है। पिछले दो दशकों में मशीनीकरण की गति तीव्र हुई है, जिससे परम्परागत कृषि श्रम की मांग में भारी कमी आई है। इस अध्ययन में 12 ग्राम पंचायतों के 480 परिवारों से प्राथमिक डेटा संकलित किया गया है। शोध में मिश्रित अनुसंधान पद्धति (Mixed Method Research) का उपयोग किया गया है, जिसमें संरचित साक्षात्कार, फोकस समूह चर्चा एवं प्रतिभागी अवलोकन शामिल हैं। अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों में यह सामने आया कि 2004–05 से 2023–24 के बीच जनपद में ट्रैक्टरों की संख्या में 312% की वृद्धि हुई, जबकि प्रति हेक्टेयर मानव-दिवस रोजगार में 62.8% की कमी आई। सर्वेक्षित परिवारों में से 67.3% परिवारों के कम से कम एक सदस्य ने प्रवास किया है। प्रवास के प्रमुख गंतव्य लखनऊ, दिल्ली, मुंबई एवं सूरत हैं। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि कृषि यंत्रीकरण एवं जाति-आधारित श्रम बाजार की संरचना मिलकर अनुसूचित जाति श्रमिकों को असमान रूप से प्रभावित करती है।

मुख्य शब्द (Keywords): *कृषि यंत्रीकरण, अनुसूचित जाति, प्रवासन पैटर्न, ग्रामीण श्रम बाजार, जाति-आधारित विस्थापन, मौसमी प्रवास, सामाजिक-आर्थिक असमानता।*

प्रस्तावना (Introduction)

भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ आज भी ग्रामीण जनसंख्या का एक बड़ा भाग जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। परन्तु पिछले कुछ दशकों में कृषि के क्षेत्र में हुए तकनीकी परिवर्तनों, विशेषकर यंत्रीकरण ने, ग्रामीण श्रम बाजार की संरचना को मूलभूत रूप से बदल दिया है। यह परिवर्तन केवल उत्पादन तकनीक में बदलाव नहीं है, अपितु यह उन समुदायों के जीवन को सीधे प्रभावित करता है जो परम्परागत रूप से कृषि श्रम पर निर्भर रहे हैं।

ग्रामीण भारत में अनुसूचित जाति समुदाय का एक बड़ा वर्ग भूमिहीन अथवा अल्पभूमिधारी होने के कारण अपनी आजीविका के लिए मुख्यतः कृषि मजदूरी पर निर्भर रहता है। कृषि कार्यों में मशीनों के बढ़ते उपयोग से पारंपरिक श्रम की मांग में कमी आई है, जिससे विशेषकर अनुसूचित जाति के कृषि श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर सीमित हुए हैं। परिणामस्वरूप, इन श्रमिकों को आजीविका की तलाश में अपने गाँवों से

- शोध छात्र, समाजशास्त्र विभाग, डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या
- सहायक आचार्य ,समाजशास्त्र विभाग, आचार्य नरेंद्र देव किसान पी. जी. कॉलेज बभनान, गोंडा

निकटवर्ती नगरों अथवा अन्य राज्यों की ओर प्रवास करने के लिए विवश होना पड़ता है। इस प्रकार कृषि यंत्रीकरण केवल तकनीकी परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण सामाजिक संरचना, रोजगार व्यवस्था तथा प्रवासन के स्वरूप को भी प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक बन गया है।

उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जनपद में भी पिछले कुछ वर्षों में कृषि यंत्रीकरण का विस्तार तेजी से हुआ है। इसके फलस्वरूप कृषि कार्यों में श्रमिकों की आवश्यकता में कमी आई है, जिसका सर्वाधिक प्रभाव अनुसूचित जाति के कृषि श्रमिकों पर पड़ा है। रोजगार की अनिश्चितता, आय में कमी तथा बेहतर जीवन-स्तर की आकांक्षा ने इन श्रमिकों के प्रवासन की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। यह प्रवासन अस्थायी, मौसमी तथा स्थायी—तीनों रूपों में देखा जा सकता है। साथ ही, प्रवासन ने श्रमिकों के आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर भी व्यापक प्रभाव डाला है।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो कृषि यंत्रीकरण और प्रवासन के मध्य संबंध केवल आर्थिक कारणों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक असमानता, जातिगत संरचना, संसाधनों तक पहुँच, शिक्षा, कौशल, सामाजिक गतिशीलता तथा जीवन-स्तर जैसे अनेक आयामों से भी जुड़ा हुआ है। अनुसूचित जाति के श्रमिकों का प्रवासन ग्रामीण समाज में बदलते शक्ति-संबंधों, रोजगार संरचना तथा सामाजिक परिवर्तन को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

वर्तमान शोध का उद्देश्य अम्बेडकर नगर जनपद में कृषि यंत्रीकरण के कारण अनुसूचित जाति श्रमिकों के प्रवासन के पैटर्न का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना है। इस अध्ययन के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया जाएगा कि कृषि यंत्रीकरण ने श्रमिकों के रोजगार, आय, सामाजिक स्थिति तथा प्रवासन की प्रकृति को किस प्रकार प्रभावित किया है। साथ ही, यह शोध नीति-निर्माताओं एवं शोधकर्ताओं के लिए ऐसे सुझाव प्रस्तुत करेगा, जिनके माध्यम से कृषि आधुनिकीकरण और ग्रामीण रोजगार के मध्य संतुलन स्थापित किया जा सके तथा अनुसूचित जाति के श्रमिकों के सतत एवं समावेशी विकास को सुनिश्चित किया जा सके।

अम्बेडकर नगर जनपद, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में स्थित है, इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अध्ययन स्थल है। यहाँ अनुसूचित जाति की जनसंख्या का अनुपात राज्य के औसत (20.7%) से अधिक (23.4%) है। यह जनपद पारम्परिक कृषि अर्थव्यवस्था से आधुनिक यंत्रीकृत कृषि की ओर संक्रमण के मध्य है। इस पृष्ठभूमि में यह शोध अध्ययन कृषि यंत्रीकरण एवं अनुसूचित जाति श्रमिकों के प्रवासन के बीच संबंध को समझने का प्रयास करता है।

उद्देश्य (Aims & Objectives)

- इस शोध अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—
- अम्बेडकर नगर जनपद में कृषि यंत्रीकरण की प्रकृति, गति एवं प्रसार का मूल्यांकन करना।
- कृषि यंत्रीकरण के कारण अनुसूचित जाति श्रमिकों के रोजगार पर पड़े प्रभावों का विश्लेषण करना।
- अनुसूचित जाति श्रमिकों के प्रवासन के विभिन्न पैटर्न (मौसमी, अर्ध-स्थायी, स्थायी) की पहचान करना।

- प्रवासन के प्रमुख कारणों (Push एवं Pull कारकों) का अध्ययन करना।
- प्रवासन के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण करना।
- अनुसूचित जाति श्रमिकों के प्रवासन में जाति-आधारित भेदभाव की भूमिका का परीक्षण करना।
- नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना जो इन समुदायों की जीवनदशा में सुधार में सहायक हों।

परिकल्पना (Hypothesis)

मुख्य परिकल्पना (Main Hypothesis)

H_1: कृषि यंत्रीकरण की वृद्धि दर एवं अनुसूचित जाति श्रमिकों की प्रवासन दर के बीच सकारात्मक एवं सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण सह-संबंध है।

उप-परिकल्पनाएँ (Sub-Hypotheses)

H_2: कृषि यंत्रीकरण का प्रभाव उच्च जातियों की तुलना में अनुसूचित जाति श्रमिकों पर अनुपातहीन रूप से अधिक है।

H_3: यंत्रीकरण से उत्पन्न विस्थापन के कारण अनुसूचित जाति श्रमिक मुख्यतः मौसमी एवं चक्रीय प्रवासन करते हैं।

H_4: प्रवासन का स्वरूप जाति, भूमि स्वामित्व एवं शैक्षिक स्तर से सांख्यिकीय रूप से प्रभावित होता है।

H_5: श्रमिक प्रवासन से मूल ग्राम में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन उत्पन्न होते हैं जो परिवार की सामाजिक स्थिति को प्रभावित करते हैं।

साहित्य समीक्षा (Review of Literature)

वैश्विक परिप्रेक्ष्य

कृषि यंत्रीकरण एवं श्रम विस्थापन का सम्बन्ध वैश्विक स्तर पर व्यापक रूप से अध्ययन किया गया *है। Binswanger (1986)* ने अपने ऐतिहासिक अध्ययन में प्रतिपादित किया कि कृषि मशीनीकरण विकासशील देशों में भूमिहीन श्रमिकों को असमान रूप से प्रभावित करता है। उनके अनुसार, यंत्रीकरण से कुशल श्रम की माँग बढ़ती है, परन्तु अकुशल श्रम, जो अनुसूचित एवं हाशिए पर स्थित समुदायों में अधिक है, की माँग घटती है।

Datt एवं Ravallion (1998) ने भारत के संदर्भ में दर्शाया कि कृषि विकास की प्रकृति सर्वसमावेशी नहीं रही है और इसके लाभ असमान रूप से वितरित हुए हैं। Harriss-White (2003) ने तमिलनाडु में किए गए अध्ययन में पाया कि यंत्रीकरण ने जाति-आधारित श्रम विभाजन को पुनर्स्थापित करने के बजाय उसे और अधिक जटिल बना दिया।

Theodore W. Schultz (1964) शुल्ट्ज़ ने अपनी पुस्तक Transforming Traditional Agriculture में यह प्रतिपादित किया कि आधुनिक कृषि तकनीकों एवं यंत्रीकरण के माध्यम से कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि

संभव है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि तकनीकी परिवर्तन ग्रामीण श्रम संरचना एवं रोजगार के स्वरूप को प्रभावित करता है।

Michael P. Todaro (1969) टोडारो ने अपने प्रसिद्ध Migration Model में बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवासन का प्रमुख कारण रोजगार एवं आय की बेहतर संभावनाएँ होती हैं। यह सिद्धांत कृषि यंत्रीकरण से उत्पन्न बेरोजगारी और प्रवासन के संबंध को समझने में अत्यंत उपयोगी है।

Harris and Todaro (1970) हैरिस एवं टोडारो ने ग्रामीण-शहरी प्रवासन के आर्थिक मॉडल को विकसित करते हुए बताया कि रोजगार के अवसरों में कमी तथा आय की असमानता ग्रामीण जनसंख्या को शहरों की ओर प्रवास के लिए प्रेरित करती है।

Bina Agarwal (1981) अग्रवाल ने कृषि यंत्रीकरण के श्रम उपयोग पर प्रभाव का अध्ययन करते हुए पाया कि मशीनों के बढ़ते उपयोग से भूमिहीन एवं कमजोर वर्गों के रोजगार में कमी आती है। विशेष रूप से महिलाओं एवं अनुसूचित जाति के श्रमिकों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव अधिक देखा गया।

Rajkhowa and Kubik (2021) इन शोधकर्ताओं ने बताया कि कृषि यंत्रीकरण का प्रभाव सभी परिस्थितियों में समान नहीं होता। इसका प्रभाव मशीनों के प्रकार, खेतों के आकार एवं श्रम की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य (Indian Perspective)

(क) कृषि यंत्रीकरण एवं रोजगार

K. N. Raj (1972) राज ने भारतीय कृषि में यंत्रीकरण के कारण श्रम की मांग में कमी तथा ग्रामीण असमानता में वृद्धि की ओर संकेत किया।

Oberai and Manmohan Singh (1982) इनका अध्ययन पंजाब में कृषि तकनीक एवं प्रवासन पर आधारित था। उन्होंने पाया कि यंत्रीकरण के कारण कृषि श्रमिकों का प्रवासन बढ़ा तथा श्रम बाजार की संरचना में परिवर्तन आया।

B. B. Mohanty (2019) मोहंती ने कृषि आधुनिकीकरण के सामाजिक प्रभावों का अध्ययन करते हुए बताया कि यंत्रीकरण से भूमिहीन एवं अनुसूचित जाति के श्रमिकों के रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(ख) अनुसूचित जाति एवं प्रवासन

S. Irudaya Rajan, Kunal Keshri and Priya Deshingkar (2023) इन शोधकर्ताओं ने भारत में जाति एवं अस्थायी प्रवासन का अध्ययन किया। अध्ययन के अनुसार अनुसूचित जाति समुदायों में आर्थिक असुरक्षा एवं रोजगार की कमी के कारण प्रवासन की दर अधिक पाई गई।

Amaresh Dubey, Richard Palmer-Jones and Kunal Sen इनका अध्ययन दर्शाता है कि ग्रामीण रोजगार की कमी, सामाजिक संरचना तथा जातिगत असमानता प्रवासन के प्रमुख निर्धारक हैं।

Farzana Afridi, Monisankar Bishnu and Kanika Mahajan (2023) इनके अध्ययन में कृषि यंत्रीकरण के कारण कृषि श्रम, विशेषकर कमजोर एवं वंचित वर्गों के रोजगार में कमी का उल्लेख किया गया है।

(ग) उत्तर प्रदेश एवं स्थानीय संदर्भ

उत्तर प्रदेश तथा विशेष रूप से अम्बेडकर नगर जनपद में कृषि यंत्रीकरण के कारण अनुसूचित जाति कृषि श्रमिकों के प्रवासन के पैटर्न पर केंद्रित शोध अत्यंत सीमित हैं। अधिकांश अध्ययन राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर तक सीमित हैं तथा स्थानीय समाजशास्त्रीय विश्लेषण का अभाव है। इसलिए यह शोध इस महत्वपूर्ण शोध-अंतर (Research Gap) को भरने का प्रयास करेगा।

Gupta (2005) ने उत्तर प्रदेश में किए गए शोध में पाया कि दलित श्रमिक परिवारों में प्रवासन की दर अन्य समुदायों की तुलना में 40% अधिक है। NSSO के 68वें दौर (2011–12) के आँकड़े भी यह पुष्टि करते हैं कि अनुसूचित जाति के परिवारों में से 45.6% आर्थिक कारणों से प्रवास करते हैं।

अम्बेडकर नगर एवं पूर्वांचल पर अध्ययन

अम्बेडकर नगर जनपद पर विशेष शोध अपेक्षाकृत सीमित है। Mishra (2018) ने पूर्वांचल क्षेत्र में कृषि संकट का अध्ययन किया था, जिसमें उन्होंने दलित परिवारों की बढ़ती निर्भरता गैर-कृषि आय पर दर्शाई थी। Singh एवं Yadav (2020) ने बताया कि इस क्षेत्र में ट्रैक्टर एवं थ्रेशर के प्रसार से बुवाई एवं कटाई के मौसमों में पारम्परिक श्रम की माँग लगभग आधी हो गई है।

शोध-अंतर (Research Gap)

उपलब्ध साहित्य से स्पष्ट होता है कि पश्चिमी अध्ययनों में कृषि यंत्रीकरण एवं प्रवासन के आर्थिक एवं संरचनात्मक पहलुओं पर अधिक बल दिया गया है, जबकि भारतीय अध्ययनों में कृषि यंत्रीकरण के रोजगार, जाति एवं ग्रामीण विकास पर प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। तथापि, अम्बेडकर नगर जनपद में कृषि यंत्रीकरण के कारण अनुसूचित जाति श्रमिकों के प्रवासन के पैटर्न का समाजशास्त्रीय अध्ययन उपलब्ध साहित्य में लगभग अनुपस्थित है। विशेष रूप से प्रवासन की प्रकृति, कारण, सामाजिक-आर्थिक परिणाम, पारिवारिक परिवर्तन एवं स्थानीय जातिगत संरचना के संदर्भ में विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है। प्रस्तुत शोध इसी शोध-अंतर को पूरा करने का प्रयास करेगा।

शोध पद्धति (Research Methodology)-

अनुसंधान अभिकल्प

इस शोध में मिश्रित अनुसंधान पद्धति (Mixed Method Research Design) का प्रयोग किया गया है। मात्रात्मक डेटा के माध्यम से व्यापक सांख्यिकीय विश्लेषण एवं गुणात्मक विधियों के द्वारा गहन अनुभवात्मक समझ विकसित की गई है। अनुसंधान अभिकल्प अनुक्रमिक व्याख्यात्मक (Sequential Explanatory) प्रकार का है।

अध्ययन क्षेत्र एवं नमूना

अम्बेडकर नगर जनपद में 5 विकास खंडों—अकबरपुर, जलालपुर, टांडा, भियांव एवं कटेहरी—से कुल 12 ग्राम पंचायतें यादृच्छिक स्तरीकृत नमूनाकरण (Stratified Random Sampling) द्वारा चुनी गईं।

नमूना श्रेणी	कुल	अनुसूचित जाति	अन्य वर्ग
गराम पंचायत	12	—	—
सर्वेख्यति परिवार	480	320 (66.7%)	160 (33.3%)
यथाअनुमगित साधकपरिवार	480	320	160

शीर्ष परत : अम्बेडकर नगर में कृषि यांत्रीकरण एवं अनुसूचित जाति श्रमिक प्रवासन

नमूना श्रेणी	कुल	अनुसूचित जाति	अन्य वर्ग
फोकस ग्रुप चर्चा	24	16	8
मुख्य सूचनादाता	36	24	12

तालिका 1: शीर्ष नमूने का विवरण

डेटा संग्रहण विधियाँ

संरचित प्रश्नावली: परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, कृषि श्रम, प्रवासन इतिहास एवं आय स्रोतों पर 68 प्रश्नों वाली प्रश्नावली।

गहन साक्षात्कार: 36 प्रमुख सूचनादाताओं के साथ 60–90 मिनट के अर्द्ध-संरचित साक्षात्कार।

फोकस ग्रुप चर्चा: प्रत्येक ग्राम में 2 FGD—एक पुरुष एवं एक महिला समूह।

प्रतिभागी अवलोकन: कृषि मौसमों में श्रम बाजार का प्रत्यक्ष अवलोकन।

द्वितीयक स्रोत: जनगणना 2011, NSSO, जिला कृषि विभाग के आँकड़े।

डेटा विश्लेषण

मात्रात्मक डेटा के विश्लेषण में SPSS 25.0 का उपयोग किया गया। सांख्यिकीय परीक्षणों में Pearson Correlation, Chi-square Test, Logistic Regression एवं ANOVA का प्रयोग किया गया। गुणात्मक डेटा का विश्लेषण Thematic Analysis पद्धति से किया गया।

शोध निष्कर्ष (Research Findings)

कृषि यंत्रीकरण की स्थिति

अम्बेडकर नगर जनपद में कृषि यंत्रीकरण की गति पिछले दो दशकों में उल्लेखनीय रही है। जिला कृषि विभाग के आँकड़ों एवं प्राथमिक सर्वेक्षण के आधार पर निम्नलिखित चित्र उभरता है।

तालिका 2: अम्बेडकर नगर में कृषि यंत्रों का प्रसार (2004-2024)

कृषि यंत्र	2004-05	2013-14	2023-24	वृद्धि(%)
ट्रैक्टर (कुल)	1,842	3,654	7,593	+312%
थ्रेसर	2,104	4,287	8,943	+325%
पावर टिलर	312	876	2,341	+650%
कमबाइन हार्वेस्टर	23	187	643	+2,696%
पम्प सेट	8,432	12,654	18,342	+118%

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विशेषकर कम्बाइन हार्वेस्टर का प्रसार अत्यन्त तीव्र गति से हुआ है। कम्बाइन हार्वेस्टर एकाकी रूप से कटाई एवं मड़ाई दोनों कार्य करता है, जो परम्परागत रूप से सर्वाधिक श्रम-गहन (Labour-intensive) कार्य थे।

कृषि श्रम रोजगार पर प्रभाव

कृषि कार्य	2004-05 (मानव-दिवस/है.)	2023-24 (मानव-दिवस/है.)	परिवर्तन (%)
भूमि तैयारी (जुताई)	12.4	3.2	-74.2%
बुवाई	8.6	4.1	-52.3%
सिचाई	6.3	2.8	-55.6%
निराई-गुड़ाई	14.7	9.3	-36.7%
कटाई	18.3	5.4	-70.5%
मड़ाई/ओसाई	11.2	1.8	-83.9%
कुल वास्षिक	71.5	26.6	-62.8%

तालिका 3: कृषि श्रम रोजगार में परिवर्तन (मानव-दिवस प्रति हैक्टेयर)

कुल कृषि श्रम रोजगार में 62.8% की कमी आई है। यह कमी जाति के अनुसार असमान रही है—अनुसूचित जाति श्रमिकों के रोजगार में 68.4% की कमी, अन्य पिछड़े वर्ग में 54.2% एवं सामान्य वर्ग में मात्र 38.6% की कमी दर्ज की गई।

प्रवासन के पैटर्न–

प्रवासन की व्यापकता

सर्वेक्षित 320 अनुसूचित जाति परिवारों में से 215 परिवारों (67.2%) के कम से कम एक सदस्य ने गत पाँच वर्षों में प्रवासन किया। इसकी तुलना में अन्य वर्गों के 160 परिवारों में से 78 (48.8%) परिवारों में प्रवासन हुआ।

प्रवासन के प्रकार

- ग्रामीण से शहरी प्रवासन
- ग्रामीण से ग्रामीण प्रवासन
- मौसमी प्रवासन
- चक्रीय (Circular) प्रवासन
- अस्थायी एवं स्थायी प्रवासन
- आर्थिक प्रवासन

प्रवासियों का प्रकार	अनुसूचित जाति (%)	अन्य वर्ग (%)
मौसमी (3-6 माह)	52.3	38.6
अल्प-स्थायी (6-12 माह)	28.4	31.2
स्थायी (>1 वर्ष)	19.3	30.2
कुल	100.0	100.0

तालिका 4: प्रवास के अनुसार प्रवासियों का प्रकार

अनुसूचित जाति श्रमिकों में मौसमी प्रवासन का अनुपात अधिक है। इसका मूल कारण यह है कि ये श्रमिक शहर में भूमि न होने के बावजूद सामाजिक बंधनों के कारण स्थायी प्रवास से बचते हैं।

प्रवास के गंतव्य–

प्रवासन का गंतव्य वह स्थान होता है जहाँ प्रवासी बेहतर रोजगार, आय, शिक्षा तथा जीवन–स्तर की खोज में जाकर बसते हैं। *Ernst Georg Ravenstein* के अनुसार अधिकांश प्रवासी निकटवर्ती आर्थिक केंद्रों तथा नगरों की ओर आकर्षित होते हैं, जहाँ रोजगार के अवसर अधिक होते हैं।

Everett S. Lee के Push-Pull Theory के अनुसार गंतव्य का चयन वहाँ उपलब्ध आकर्षक सुविधाओं, जैसे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा के आधार पर होता है।

Michael P. Todaro के अनुसार ग्रामीण श्रमिक अपेक्षित आय (Expected Income) की संभावना के कारण शहरी क्षेत्रों को अपना प्रमुख गंतव्य बनाते हैं। कृषि यंत्रीकरण की स्थिति में भी अतिरिक्त श्रमिक प्रायः निकटवर्ती शहरों, औद्योगिक क्षेत्रों तथा महानगरों की ओर प्रवास करते हैं, जहाँ उन्हें वैकल्पिक रोजगार की संभावना अधिक दिखाई देती है। यही कारण है कि गंतव्य का चयन आर्थिक अवसरों, सामाजिक सुविधाओं तथा जीवन–स्तर में सुधार की अपेक्षा से प्रभावित होता है।

गंतव्य	प्रवासियों का %	प्रमुख व्यवसाय
दिल्ली-NCR	34.2%	निर्माण श्रमिक, कारखाना मजदूर
मुंबई	18.7%	निर्माण, बंदरगाह श्रमिक
सूरत	14.3%	कपड़ा उद्योग
लखनऊ	11.8%	निर्माण, घरेलू सेवा
पंजाब/हरियाणा	9.6%	कृषि श्रम (रबी मौसम)
अन्य राज्य	7.4%	विविध
जनपद के भीतर	4.0%	शहरी श्रम

तालिका 5: प्रवासन के प्रमुख गंतव्य एवं व्यवसाय

प्रवासन के कारण (Push एवं Pull कारक)

Push कारक — ग्राम से धकेलने वाले:

- कृषि यंत्रीकरण से कृषि श्रम की मांग में कमी (89.3% परिवारों द्वारा उल्लिखित)
- अपर्याप्त एवं अनियमित कृषि मजदूरी (74.6%)
- भूमि स्वामित्व का अभाव एवं बंटाईदारी की असुरक्षित स्थिति (68.2%)
- जाति-आधारित भेदभाव एवं सामाजिक अपमान (52.4%)
- ग्रामीण ऋणग्रस्तता (43.7%)
- सूखा एवं अनियमित वर्षा (38.1%)

Pull कारक — शहर की ओर आकर्षित करने वाले:

- अपेक्षाकृत अधिक एवं नियमित मजदूरी (91.2%)
- जाति-आधारित भेदभाव से अपेक्षाकृत मुक्ति (63.8%)
- बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा के अवसर (48.3%)
- स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता (34.7%)
- सामाजिक गतिशीलता की सम्भावना (29.6%)

प्रवासन का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

सकारात्मक प्रभाव:

- प्रेषण (Remittance) से पारिवारिक आय में औसतन 34.7% की वृद्धि।
- बच्चों की शिक्षा में निवेश — प्रवासी परिवारों में स्कूल उपस्थिति 18% अधिक।
- गृह निर्माण एवं सामाजिक प्रतिष्ठा में सुधार।
- कुछ परिवारों में छोटे व्यकृषि उत्पादन में वृद्धि – आधुनिक कृषि यंत्रों के प्रयोग से उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होती है।
- समय एवं श्रम की बचत – ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर आदि के उपयोग से कृषि कार्य कम समय में पूरे हो जाते हैं।
- कृषि लागत में कमी – दीर्घकाल में मशीनों के उपयोग से प्रति इकाई उत्पादन लागत कम हो सकती है।
- फसल चक्र में सुधार – समय पर बुवाई एवं कटाई होने से एक वर्ष में अधिक फसलें लेना संभव होता है।
- कृषि का आधुनिकीकरण – नई तकनीकों के उपयोग से कृषि अधिक वैज्ञानिक एवं प्रतिस्पर्धी बनती है।
- ग्रामीण अवसंरचना का विकास – कृषि यंत्रों से जुड़े उद्योग, मरम्मत केंद्र एवं सेवा क्षेत्र का विस्तार होता है।

- कृषकों की आय में वृद्धि – विशेषकर मध्यम एवं बड़े किसानों की उत्पादकता और आय बढ़ती है।वसाय एवं स्वरोजगार का सृजन।

नकारात्मक प्रभाव:

- कृषि श्रमिकों के रोजगार में कमी – मशीनों के कारण पारंपरिक कृषि श्रम की मांग घट जाती है।
- अनुसूचित जाति श्रमिकों पर अधिक प्रभाव – भूमिहीन एवं कृषि मजदूरी पर निर्भर अनुसूचित जाति के श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।
- प्रवासन में वृद्धि – रोजगार की कमी के कारण श्रमिक शहरों एवं अन्य राज्यों की ओर पलायन करते हैं।
- आर्थिक असमानता में वृद्धि – बड़े किसान मशीनों का लाभ अधिक उठाते हैं, जबकि छोटे किसान एवं मजदूर अपेक्षाकृत पीछे रह जाते हैं।
- सामाजिक असुरक्षा – बेरोजगारी के कारण गरीबी, ऋणग्रस्तता एवं सामाजिक समस्याएँ बढ़ सकती हैं।
- पारिवारिक एवं सामाजिक विघटन – प्रवासन के कारण परिवारों का विखंडन, बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव तथा सामाजिक संबंध कमजोर हो सकते हैं।
- महिला श्रमिकों पर प्रतिकूल प्रभाव – निराई, कटाई एवं अन्य कार्यों में मशीनों के उपयोग से महिलाओं के रोजगार के अवसर भी कम हो जाते हैं।
- कौशल असमानता – मशीनों के संचालन के लिए तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है, जिससे अशिक्षित एवं अकुशल श्रमिक पीछे रह जाते हैं।

विश्लेषण एवं चर्चा (Discussion)

सांख्यिकीय परीक्षण

Pearson Correlation विश्लेषण से ट्रैक्टर घनत्व एवं प्रवासन दर के बीच $r = 0.743$ ($p < 0.001$) का सकारात्मक सह-संबंध पाया गया, जो मुख्य परिकल्पना H_1 की पुष्टि करता है। Logistic Regression विश्लेषण यह दर्शाता है कि अनुसूचित जाति का सदस्य होना प्रवासन की संभावना को 2.3 गुना बढ़ा देता है (OR = 2.31, 95% CI: 1.87–2.89)।

Chi-square परीक्षण ($\chi^2 = 34.67$, df = 4, $p < 0.001$) यह पुष्टि करता है कि प्रवासन का प्रकार (मौसमी/अर्ध-स्थायी/स्थायी) जाति वर्ग से सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण रूप से सम्बद्ध है।

सैद्धान्तिक विमर्श

इस शोध के निष्कर्षों को दोहरे श्रम बाज़ार सिद्धान्त *(Dual Labour Market Theory — Piore, 1979)* *एवं* विश्व प्रणाली सिद्धान्त *(World Systems Theory — Wallerstein, 1974)* के आलोक में समझा जा सकता है। अम्बेडकर नगर जैसे पिछड़े जनपदों से श्रमिकों का महानगरों की ओर प्रवाह वैश्विक पूँजीवाद की उस प्रवृत्ति का स्थानीय प्रतिरूप है।

परन्तु भारतीय संदर्भ में इस प्रक्रिया में जातिगत विशिष्ट आयाम जुड़ जाता है। Ambedkar (1936) ने यह रेखांकित किया था कि जाति व्यवस्था श्रम का विभाजन नहीं, बल्कि श्रमिकों का विभाजन है। कृषि यंत्रीकरण की प्रक्रिया इस विभाजन को आर्थिक आधार पर पुनरुत्पादित करती है।

लिंग आयाम

शोध में यह भी पाया गया कि जब पुरुष प्रवास करते हैं, तो महिलाएँ गाँव में रहकर कृषि कार्यों का प्रबंधन करती हैं। किन्तु यंत्रीकरण के कारण कृषि में महिला श्रम की माँग भी कम हुई है। निराई-गुड़ाई को छोड़कर, जो अभी भी महिला-केन्द्रित है, अधिकांश कृषि कार्य यंत्रीकृत हो चुके हैं। इससे ग्रामीण महिलाओं की आय में कमी एवं उनकी आर्थिक कमजोरी बढ़ी है।

निष्कर्ष (Conclusion)

यह शोध अध्ययन स्पष्ट रूप से प्रतिपादित करता है कि अम्बेडकर नगर जनपद में कृषि यंत्रीकरण एवं अनुसूचित जाति श्रमिकों के प्रवासन के बीच एक सुदृढ़ कार्य-कारण सम्बन्ध विद्‌यमान है। यंत्रीकरण ने परम्परागत कृषि श्रम को प्रतिस्थापित किया है, जिसका भार असमान रूप से अनुसूचित जाति समुदाय पर पड़ा है। प्रस्तुत शोध से यह स्पष्ट होता है कि कृषि यंत्रीकरण ने अम्बेडकर नगर जनपद की कृषि व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। आधुनिक कृषि यंत्रों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर तथा अन्य मशीनों के उपयोग से कृषि उत्पादन, कार्यकुशलता तथा समय की बचत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इससे कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण को गति मिली तथा किसानों, विशेषकर मध्यम एवं बड़े कृषकों, को आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ।

इसके विपरीत, कृषि यंत्रीकरण का सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव भूमिहीन एवं कृषि मजदूरी पर निर्भर अनुसूचित जाति श्रमिकों पर पड़ा है। मशीनों द्‌वारा पारंपरिक श्रम का स्थान लेने से कृषि श्रमिकों के रोजगार के अवसरों में कमी आई, जिसके परिणामस्वरूप अनेक श्रमिकों को आजीविका की तलाश में गाँव छोड़कर निकटवर्ती नगरों अथवा अन्य राज्यों की ओर प्रवास करना पड़ा। अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि इन श्रमिकों का प्रवासन मुख्यतः आर्थिक कारणों से प्रेरित है, किन्तु इसके पीछे सामाजिक असमानता, सीमित संसाधन, शिक्षा एवं कौशल की कमी तथा बेहतर जीवन स्तर की आकांक्षा जैसे अन्य कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

शोध से यह भी ज्ञात होता है कि अनुसूचित जाति श्रमिकों का प्रवासन केवल आर्थिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव उनके पारिवारिक जीवन, सामाजिक संबंधों, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामुदायिक संरचना पर भी पड़ता है। एक ओर प्रवासन से कुछ परिवारों की आय में वृद्धि होती है और नए रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, वहीं दूसरी ओर परिवारों का विखंडन, सामाजिक असुरक्षा तथा सांस्कृतिक परिवर्तन जैसी समस्याएँ भी सामने आती हैं।

अतः यह कहा जा सकता है कि कृषि यंत्रीकरण का प्रभाव द्‌वैध (Dual) है। जहाँ यह कृषि विकास एवं उत्पादकता वृद्धि का प्रभावी साधन है, वहीं दूसरी ओर यह ग्रामीण श्रमिकों, विशेषकर अनुसूचित जाति समुदाय के लिए रोजगार एवं आजीविका की नई चुनौतियाँ भी उत्पन्न करता है। इसलिए आवश्यक है कि कृषि आधुनिकीकरण के साथ-साथ ग्रामीण रोजगार सृजन, कौशल विकास, वैकल्पिक आजीविका, सामाजिक सुरक्षा

योजनाओं तथा अनुसूचित जाति श्रमिकों के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए। इससे कृषि विकास और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकेगा तथा समावेशी एवं सतत ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा।

इस प्रकार, प्रस्तुत अध्ययन अम्बेडकर नगर जनपद में कृषि यंत्रीकरण और अनुसूचित जाति श्रमिकों के प्रवासन के बीच संबंधों को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समझने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है तथा भविष्य के शोध एवं नीति-निर्माण के लिए उपयोगी आधार प्रस्तुत करता है।

प्रवास मुख्यतः आर्थिक विवशता से उत्पन्न है, न कि स्वैच्छिक इच्छा से। यह प्रवास न केवल व्यक्ति और परिवार, बल्कि सम्पूर्ण ग्रामीण सामाजिक संरचना को प्रभावित करता है। यद्यपि प्रवासी आय से कुछ परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, तथापि यह दीर्घकालीन समाधान नहीं है।

मूल समस्या यह है कि कृषि यंत्रीकरण की प्रक्रिया में जाति-आधारित श्रम बाज़ार की संरचना ने अनुसूचित जाति श्रमिकों को नई तकनीकों के अनुकूलन के अवसरों से वंचित रखा है। अतः आवश्यकता है कि सामाजिक न्याय के परिप्रेक्ष्य से कृषि नीति निर्माण किया जाए।

नीतिगत सुझाव (Policy Recommendations)

- कृषि यंत्र बैंक (Farm Machinery Banks) की स्थापना विशेष रूप से अनुसूचित जाति समूहों के लिए की जाए ताकि वे यंत्रीकरण के लाभार्थी बन सकें।
- कृषि यंत्र प्रशिक्षण केन्द्रों में अनुसूचित जाति युवाओं के लिए आरक्षण एवं विशेष छात्रवृत्ति का प्रावधान किया जाए।
- MGNREGS के अंतर्गत कृषि-संबंधित कार्यों में गारंटीशुदा रोजगार दिनों को 100 से बढ़ाकर 150 किया जाए।
- प्रवासी श्रमिकों के लिए पोर्टेबल सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ बनाई जाएँ जो उनके गृह जनपद एवं कार्य स्थल दोनों पर लागू हों।
- भूमि सुधार कार्यक्रमों को पुनः सक्रिय किया जाए एवं भूमिहीन अनुसूचित जाति परिवारों को कृषि भूमि आवंटित की जाए।
- ग्रामीण क्लस्टरों में गैर-कृषि उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाए जिससे स्थानीय रोजगार के अवसर उत्पन्न हों।
- Inter-State Migrant Workmen Act, 1979 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
- ग्रामीण रोजगार सृजन: कृषि के अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर विकसित किए जाएँ।
- कौशल विकास: अनुसूचित जाति श्रमिकों को तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

- मनरेगा को सुदृढ़ करना: वर्षभर स्थानीय रोजगार उपलब्ध कराने हेतु मनरेगा का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
- सामाजिक सुरक्षा: प्रवासी श्रमिकों को बीमा, पेंशन, स्वास्थ्य एवं राशन जैसी सुविधाएँ सुनिश्चित की जाएँ।
- कृषि यंत्रों पर सब्सिडी: छोटे एवं सीमांत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद हेतु वित्तीय सहायता दी जाए।
- कस्टम हायरिंग सेंटर: सामुदायिक कृषि यंत्र बैंक स्थापित किए जाएँ ताकि छोटे किसान भी मशीनों का उपयोग कर सकें।
- ग्रामीण औद्योगीकरण: कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर स्थानीय रोजगार बढ़ाया जाए।
- शिक्षा एवं कौशल उन्नयन: युवाओं को रोजगारोन्मुखी शिक्षा एवं डिजिटल कौशल से जोड़ा जाए।
- प्रवासी श्रमिक कल्याण: प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों, उचित वेतन एवं सुरक्षित कार्य परिस्थितियों को सुनिश्चित किया जाए।
- समावेशी कृषि नीति: कृषि यंत्रीकरण के साथ रोजगार संरक्षण एवं सामाजिक न्याय को भी नीति का हिस्सा बनाया जाए.
- स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा: अनुसूचित जाति समुदाय के लिए स्वरोजगार एवं उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जाए।
- सरकार–समुदाय समन्वय: सरकार, पंचायत एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से श्रमिक कल्याण कार्यक्रम प्रभावी ढंग से लागू किए जाएँ।

सन्दर्भ सूची (References)

1. Ambedkar, B. R. (1936). Annihilation of Caste. Self-published.
2. Binswanger, H. P. (1986). Agricultural mechanization: A comparative historical perspective. The World Bank Research Observer, 1(1), 27–56.
3. Breman, J. (1996). Footloose Labour: Working in India’s Informal Economy. Cambridge University Press.
4. Datt, G., & Ravallion, M. (1998). Farm productivity and rural poverty in India. Journal of Development Studies, 34(4), 62–85.
5. Gupta, D. (2005). Whither the Indian village: Culture and agriculture in rural India. Economic and Political Weekly, 40(8), 751–758.
6. Harriss-White, B. (2003). India Working: Essays on Society and Economy. Cambridge University Press.
7. Mishra, S. K. (2018). Agrarian Crisis and Dalit Migration in Eastern Uttar Pradesh. Economic and Political Weekly, 53(12), 43–51.

8. National Sample Survey Office (NSSO). (2012). Employment and Unemployment Situation in India (NSS 68th Round). Government of India.
9. Piore, M. J. (1979). Birds of Passage: Migrant Labour and Industrial Societies. Cambridge University Press.
10. Singh, R. K., & Yadav, A. (2020). Agricultural mechanization and rural labour displacement in Purvanchal region. Indian Journal of Rural Development, 39(2), 112–134.
11. Wallerstein, I. (1974). The Modern World-System I. Academic Press.
12. Deshingkar, P., & Start, D. (2003). Seasonal Migration for Livelihoods in India: Coping, Accumulation and Exclusion. Overseas Development Institute (ODI), London.
13. Deshingkar, P. (2006). Internal Migration, Poverty and Development in Asia. Overseas Development Institute (ODI).
14. Rogaly, B., Biswas, J., Coppard, D., Rafique, A., Rana, K., & Sengupta, A. (2001). Seasonal Migration, Social Change and Migrants' Rights. University of Sussex.
15. Jodhka, S. S. (2012). Caste. Oxford University Press.
16. Shah, G., Mander, H., Thorat, S., Deshpande, S., & Baviskar, A. (2006). Untouchability in Rural India. Sage Publications.
17. Patnaik, U. (2007). The Republic of Hunger and Other Essays. Three Essays Collective.
18. Mohanty, B. B. (2013). Agricultural Modernization, Rural Labour and Migration in India. Indian Journal of Labour Economics, 56(2), 235–252.
19. National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD). (2021). All India Rural Financial Inclusion Survey (NAFIS 2021-22).
20. NITI Aayog. (2021). Doubling Farmers' Income: Progress and Challenges. Government of India.
21. Ministry of Agriculture & Farmers Welfare. (2023). Agricultural Statistics at a Glance 2023. Government of India.
22. जिला कृषि विभाग, अम्बेडकर नगर। (2024). वार्षिक कृषि प्रतिवेदन 2023–24. उत्तर प्रदेश शासन।
23. जनगणना 2011। (2013). प्राथमिक जनगणना सार, अम्बेडकर नगर. भारत सरकार, रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय।

अमन वर्मा ईमेल
डॉ0 सुधांशु वर्मा